दीपक सक्सेना, कौशलेन्द्र सचिव पद पर पदोन्नत

वर्ष 2002, 2010, 2013 और 2022 बैच के आईएएस को पदोन्नत करने मंत्रालय में हुई डीपीसी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 दिसंबर. भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार बैच के अफसरों को पदोन्नत करने के लिये गुरुवार को मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई.

बैठक में 2002, 2010, 2013 और 2022 बैच के ज्यादातर नामों को हरी झंडी दे दी गई. वर्ष 2002 बैच के दो अफसरों के प्रमुख सचिव बनने का रास्ता साफ हो गया. इनमें से भी मप्र में पदस्थ सचिव कार्मिक एम.सेलवेन्द्रम को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया, इसी बैच के अजीत कुमार जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनको प्रोफार्मा पदोन्नति देने पर सहमति बनी.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वर्ष 2002 बैच में महज दो ही आईएएस हैं. इस तरह इस बार की डीपीसी में प्रदेश को एक ही प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी मिला है. इससे आने वाले समय में कई विभागों का दारोमदार सचिव स्तर के अधिकारियो के कंधे पर रहेगा. डीपीसी मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई. जिसमें एसीएस डॉ. राजेश राजौरा भी शामिल हुए. पदोन्नति संबंधी आदेश शीघ्र ही जारी होने की संभावना है.

डीपीसी में शामिल सबसे महत्वपूर्ण बैच 2010 का था, इस बैच में अपर सचिव स्तर के 20 अधिकारी हैं. बताया जा रहा है कि इस बैच में कुल 17 नामों को सचिव पद पर पदोन्नति के लिये हरी झंडी दी गई. इस बैच में तीन अफसरों के नाम रोक दिये गए. जिन अफसरों को सचिव पद पदोन्नत करने पर सहमति बनी है, उनमें आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना, भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, स्वास्थ्य आयुक्त तरूण राठी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी, कमिश्नर फूड कर्मवीर शर्मा, अपर सचिव पिछड़ा वर्ग विभाग अनुराग चौधरी, कमिश्नर कोष एवं लेखा भास्कर लक्षकार, कमिश्नर ग्वालियर संभाग अभिजीत अग्रवाल, कमिश्नर उज्जैन संभाग आशीष सिंह, डायरेक्टर स्वास्थ्य दिनेश श्रीवास्तव, सचिव राजस्व मंडल ग्वालियर सपना निगम, चंबल कमिश्नर सुरेश कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चंद्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग शीलेन्द्र सिंह शामिल हैं.

> 2013 बैच के अफसरों को अपर सचिव के पद पर पदोन्नत करने पर सहमति बन गई है. इस बैच में कुल 27 अफसर थे, जिनके नामों पर विचार किया गया. इसमें से 10 अधिकारी अभी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं, इनमें इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह भी शामिल हैं. इनके अलावा प्रियंक मिश्रा, अमनबीर बैंस, ऋषि गर्ग, रजनी सिंह, मयंक अग्रवाल, सोनिया मीना, सतीश कुमार एस., फ्रेंक नोबल ए., सोमेश मिश्रा, एस. कृष्णा चैतन्य, अनूप कुमार सिंह, हर्ष दीक्षित, संदीप जीआर. गिरीश कुमार मिश्रा, उमा माहेश्वरी आर., विकास मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, मीनाक्षी सिंह, कैलाश वानखेड़े, अमर बहादुर सिंह, मनीषा सेंतिया, नीरज कुमार वशिष्ठ, किशोर कुमार कान्याल, रूही खान, पवन कुमार जैन के नाम शामिल हैं.

दिसंबर में कड़ाके की ठंड

एमपी में दिसंबर भर जमाएगी ठंड-

जेट स्ट्रीम से पारा 3-7 डिग्री तक गिरा

भोपाल, 11 दिसंबर. मध्यप्रदेश में इस साल दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है.

हिमालयी क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी भारत में तेज जेट स्ट्रीम के कारण राज्य भर में तापमान तेजी से नीचे आ रहा है. कई शहरों में पारा 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे प्रदेश के बड़े हिस्से में शीतलहर की स्थिति बन गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार दिसंबर सामान्य से अधिक ठंडा रहने वाला है. समय से पहले हुई बर्फबारी, ला नीना पैटर्न और उत्तरी हवाओं की वजह से यह ठंड और तीव्र महसूस हो रही है.

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण दोपहर तक कड़ाके की ठंड बनी रही. भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर और शहडोल जिलों में शीतलहर दर्ज की गई, जबकि इंदौर जिले में तीव्र शीतलहर का प्रभाव देखने को मिला. अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ, हालांकि इंदौर और उज्जैन संभागों में यह सामान्य से 1.7 डिग्री तक कम रहा. न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिक स्पष्ट रही. भोपाल संभाग में यह सामान्य से 5.1 डिग्री तक नीचे रहा. इंदौर और उज्जैन में रात का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री से 3.4 डिग्री तक कम रिकॉर्ड हुआ.

> नर्मदापुरम, चंबल, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री से 2.9 डिग्री तक नीचे रहा. मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के ऊपर 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 204 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उपोष्ण जेट स्ट्रीम बह रही है. जिसका असर मध्यप्रदेश तक दिख रहा है. 13 दिसंबर से एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में कई दिनों तक ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी.

एक नजर में

विधायक को धमकी देने वाले ने किया सरेंडर

शिवपुरी. जिले के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा को धमकी देने के आरोपी ने शिवपुरी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि आरोपी प्रभात रावत कुख्यात बदमाश है. वो पूर्व में भी आपराधिक मामले में फरार चल रहा था. सूत्रों ने बताया कि चार दिन पूर्व उसने जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक कैलाश कुशवाहा को फोन पर धमकी दी थी. विधायक के इस मामले में पुलिस में शिकायत कर दिए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी थी.

अवैध गांजा के साथ तीन बंदी

पन्ना. जिले में पुलिस ने बिक्री हेतु गांजा ले जाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 5 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा एवं एक मोटरसाइकिल सहित करीब 2 लाख 15 हजार रुपये का सामान जब्त किया गया है.

सिक्किम को 400 ईवीएम देगा एमपी

ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत किराए पर उपलब्ध कराने किया एमओयू

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 दिसंबर. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ईव्हीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत किराये पर सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग को 400 ईवीएम उपलब्ध करायेगा.

इस संबंध में गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की उपस्थिति में सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह और सचिव सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग सुश्री ग्लोरिया नामचू ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये. राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि ईवीएम शेयरिंग के मामले में मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट है. उन्होंने बताया कि ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम किराये पर दी जा चुकी हैं. इसी तरह जम्मू-कश्मीर एवं महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन को भी ईवीएम किराये पर देने के लिये एमओयू हो चुका है.

अन्य राज्यों के साथ भी एमओयू की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी को-ऑपरेटिव फेडरेलिजम का बेहतर उदाहरण है. श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. उन्होंने कहा कि आज के एमओयू से सिक्किम और मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे.

> सचिव सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग सुश्री नामचू ने कहा कि यह पॉलिसी सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिये बहुत उपयोगी है. सुश्री नामचू ने कहा कि इससे राज्यों का आर्थिक बोझ कम होगा और सरलता से स्थानीय चुनाव कराये जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जा रहीं निर्वाचन की अन्य नवीनतम तकनीकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसका उपयोग सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा.

सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर भोपाल-इंदौर में होंगे कार्यक्रम

13 को भोपाल और 14 को इंदौर में होगा कार्यक्रम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 13 दिसंबर को भोपाल और 14 दिसंबर को इंदौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

प्रदेश में सरकार बनने के बाद गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए. राज्य में कृषि के लिए सिंचाई का रकबा दोगुना करने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान और कई बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास जारी हैं. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है. हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिये रवाना होने से पहले इंदौर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में सुशासन पर आधारित व्यवस्थाएं संचालित हों, इसके लिए अच्छे कार्य में सदैव साथ हैं और अगर कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.

नीट पीजी काउंसलिंग के पहले चरण का परिणाम घोषित

भोपाल. चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भोपाल ने एमपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। आवंटन में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदौर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर अभ्यर्थियों की पहली पसंद में शामिल रहे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है. उन्हें 12 दिसंबर तक संबंधित मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होकर प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को आवेदनपत्र की प्रति, स्कोरकार्ड, जन्म प्रमाण, मूल निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

एनआरआई श्रेणी के लिए ओसीआई कार्ड (विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का नागरिक) की प्रति, रोटेटरी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और सेवाधीन उम्मीदवारों के लिए अनुपति पत्र जमा करना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश में आर्थिक संकट गहराने का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 11 दिसंबर. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर और अभूतपूर्व संकट बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग 165 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है और उससे भी चिंताजनक बात यह है कि पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी नए ऋण लिए जा रहे हैं.

> पटवारी ने कहा कि सरकार अब तक 101 सार्वजनिक संपत्तियों को बेच चुकी है, जिससे लगभग 1,100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इनमें राज्य से बाहर स्थित मूल्यवान संपत्तियाँ भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई और केरल की कीमती जमीनों को चुपचाप नीलाम कर दिया गया, जो वित्तीय संकट की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बेतहाशा कर्ज लेने की यह नीति आने वाली पीढ़ियों पर भारी बोझ डालेगी। अभी इसके प्रभाव भले दिखाई न दें, लेकिन इसका सीधा असर मध्यप्रदेश के लोगों के भविष्य पर पड़ेगा।